

पुतिलिपि जादेश दिनांक 11-8-14 पारित द्वारा श्रो आडेक शिष्यहरे  
सदस्य राजस्व नंगडल मध्यू० रवालियर पुष्ट० निः० 2208-तीन०/14  
विरुद्ध जादेश दिनांक 18-7-14 पारित द्वारा अर आयुक्त रावा  
सभाग रोजा पुष्ट० 516/आ०ल०/13-14.

---

हर ईश्वर श्रीवास्तव तन्य रामैश्वर पूसाद  
निवासो ग्राम सारा तहसील हुजूर जिला  
रोवा मध्य०

--- आवेदक

किंच

म०पु० शासन अन्य-४

-- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

रथान तथा  
दिनांक

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2208— तीन / 2014

कार्यवाही तथा आदेश

जिला रीवा

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों के  
हस्ताक्षर

11.8.14

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क्र0 516/13-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक एवं म0प्र0शासन के पैनल अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्कों में बताया कि ग्राम सगरा तहसील हुजूर रिथत भूमि सर्वे क्रमांक 1730 रकवा 0.28 ए. एवं 1731 रकवा 1.33 ए. के अंश भाग 0.26 ए. कुल रकवा 0.54 ए. उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19-6-80 से क्रय किया है। ग्राम सगरा की भूमि सर्वे नंबर 1730 एवं 1731 के पश्चिम की ओर शासकीय भूमि है जिस पर रीवा-सिरमौर के लिये खसरा क्रमांक 1694 में सङ्क है, किन्तु तत्समय गलत ढंग से आवेदक की भूमि में रास्ता व सङ्क का इन्द्राज कर दिया गया, जिसकी दुरुरत्ती का आवेदन तहसीलदार को दिया तथा तहसीलदार हुजूर ने स्वयं जांच किये बिना पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का इन्द्राज दुरुरत्ती का दावा निरस्त कर दिया। इसके बाद आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के न्यायालय में अपील की, वह भी निरस्त हुई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील की गई जिसमें आवेदक को स्थगन दिया गया, किन्तु ग्रामीणों द्वारा पक्षकार बनाये जाने एवं स्थगन रिक्त करने की मांग को स्वीकार कर आवेदक के पक्ष में दिया गया स्थगन अकारण रिक्त किया गया है यदि आवेदक के हित में स्थगन नहीं दिया गया तो अपील का सार ही समाप्त हो जावेगा और आवेदक की भूमि पर ग्रामीणों के आवागमन से बोई गई फसल चौपट हो जावेगी। इसलिये अपर आयुक्त का अंतरिम आदेश दिनांक

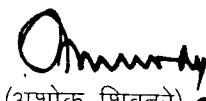
18-7-14 निरस्त कर अपील प्रकरण के निराकरण तक आवेदक के हित में स्थगन यथावत बना रहने दिया जावे।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क्र0 516/13-14 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-14 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने अंतरिम आदेश दिनांक 18-7-14 में अंकित किया है कि मौके पर ग्रामीणों का रास्ता आवेदक द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है एंव प्रचलित रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो एंव रास्ता चालू बना रहे। विचार योग्य बिन्दु है कि अपर आयुक्त द्वारा उक्तानुसार निर्णय लेने में किसी प्रकार की त्रुटि की है –

**भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)** – धारा 52 – रोक आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। इस विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिये और रोक के आदेश से प्रकट होना चाहिये कि न्यायालय ने गामले के तथ्यों और विवादित प्रश्नों पर विचार किया है।

अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपील प्रकरण में सार्वजनिक सुखाचार के रास्ते को अवरोधित न करने एंव पूर्ववत् बनाये रखने का अंतरिम आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

  
(अशोक श्रीवहरे)  
सदस्य  
राजस्व मण्डल, ग्वालियर